कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–35, अंक – 20 | अक्टूबर 16–31, 2021 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–6

किसान आंदोलन – वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ता

मज़दूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित दूसरी बैठक

26 सितंबर को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के लगातार विरोध प्रदर्शन को 10 महीने पूरे हुए। 28 सितंबर को मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) ने "किसान आंदोलन : वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ता" विषय पर दूसरी ऑनलाइन बैठक आयोजित की।

बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों के साथ–साथ ब्रिटेन और कनाडा के लोगों ने भी भाग लिया। बैठक में मणिपुर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली–एन.सी.आर., महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों से कार्यकर्ता मौजूद थे। निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष में शामिल कई सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियनों के नेताओं ने बैठक में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। महिला संगठनों, किसान संगठनों, युवा संगठनों और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने वाले संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बैठक और विचार–विमर्श में सक्रियता से भाग लिया।

बैठक का संचालन एम.ई.सी. की ओर से सुचरिता जी ने किया। उन्होंने मुख्य वक्ता, श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल, अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ (सिधुपुर) का परिचय कराया, जो इस समय किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठनों में से एक के नेता हैं। उन्होंने अन्य संगठनों के नेताओं के नामों की भी घोषणा की जिन्हें किसान आंदोलन के समर्थन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था।

सिंघू बॉर्डर में किसान आंदोलन की सभा (फाइल फोटो)

बैठक में कॉमरेड हरभजन चीमा सहित कनाडा में ईस्ट इंडियन डिफेंस कमेटी (ई.आई.डी.सी.) के कई साथियों ने भाग लिया। ये कामरेड 1970 के दशक में कनाडा में हिन्दोस्तानियों पर राज्य–आयोजित नस्लवादी हमलों के ख़िलाफ़ संघर्ष में सबसे आगे थे, जिसके कारण 1973 में ई.आई.डी.सी. की स्थापना हुई थी। ई.आई.डी.सी. ने हिन्दोस्तानी समुदाय के हजारों महिलाओं और पुरुषों को राज्य द्वारा आयोजित नस्लवादी हमलों के ख़िलाफ़ संघर्ष के लिए, "आत्मरक्षा ही एकमात्र तरीका है!" के नारे के साथ संगठित किया था। आज ये कामरेड हिन्दोस्तान में किसान आंदोलन और मज़दूरों के संघर्ष के समर्थन में कनाडा में हिन्दोस्तानी समुदाय को संगठित करने में सबसे आगे हैं। सुचरिता जी ने कहा कि कनाडा में हिन्दोस्तानी समुदाय की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने वाले कामरेडों का बैठक में उपस्थित होना बड़े सम्मान की बात है।

श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल ने इस बैठक को आयोजित करने और विदेशों में मज़दूरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और देशभक्त हिन्दोस्तानियों के व्यापक दर्शकों को जुटाने के लिए एम.ई.सी. को धन्यवाद दिया। उन्होंने किसान आंदोलन की अब तक की प्रक्रिया, तीन किसान विरोधी कानूनों को निरस्त किए जाने तक किसानों की एकता और दृढ़ संकल्प, राज्य द्वारा फैलाए गए झूठ और विरोध करने वाले किसानों पर किए गए दमन, और किसानों की एकता को तोड़ने के लिए राज्य के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बड़े हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों की निगाहें हिन्दोस्तान में कृषि क्षेत्र पर हमेशा भारी मुनाफे के स्रोत के रूप में रही हैं। उन्होंने बताया की कृषि पर बड़े इजारेदार घरानों के प्रभुत्व का विरोध लगभग 30 साल पहले, हिन्दोस्तान में निजीकरण कार्यक्रम के पहले चरण के संघर्ष से जारी है।

शेष पृष्ठ 3 पर

एयर इंडिया का निजीकरण :

इजारेदार पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़े कमाने की लालच को पूरा करने के लिए मज़दूर–विरोधी और जन–विरोधी क़दम

एयर इंडिया और इसकी सहायक इकाई ए.आई. एक्सप्रेस, जिनके पास 94 विमान हैं और जो 100 से अधिक घरेलू उड़ानों और 60 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालन करती है, इन्हें टाटा समूह को बेच दिया गया है।

टाटा ने केवल 18,000 करोड़ रुपये (लगभग 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर) की बोली लगाकर यह सफलता पाई है। उन्हें इस राशि का 15 प्रतिशत यानी मात्र 2,700 करोड़ रुपये ही सरकार को नगद देने होंगे। शेष 15,300 करोड़ रुपये से एयर इंडिया के बकाया क़र्जों को चुकाना होगा हालांकि एयर इंडिया का कुल क़र्जा, लगभग 60,000 करोड़ रुपये का है। एयर इंडिया की शेष क़र्ज राशि का वहन सरकार करेगी।

कॉरपोरेट मीडिया इस सौदे को ऐसे पेश कर रहा है जैसे कि टाटा समूह एयर इंडिया को अपने कब्ज़े में लेकर, देश पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। यह विचार

एयर इंडिया के पायलटों की हड़ताल (फाइल फोटो)

सरासर ग़लत है जिसे सच्चाई को छिपाने के लिए फैलाया जा रहा है।

सच तो यह है कि टाटा को लाभ पहुंचाने के लिए अत्यंत मूल्यवान सार्वजनिक संपत्ति को सस्ते में बेचा गया है। एयर इंडिया के 31 मार्च, 2020 तक के खातों के अनुसार उसकी शुद्ध संपत्ति 46,000 करोड़ रुपए है। देश और विदेश में ज़मीन पर उतरने और पार्किंग के सभी मूल्यवान अधिकारों के साथ–साथ उसकी भौतिक संपत्ति का वास्तविक मूल्य कई गुना अधिक है।

एयर इंडिया के पास घरेलू हवाई अड्डों पर, 4,400 घरेलू और 1,800 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये ज़मीन पर उतरने और

शेष पृष्ठ 2 पर

अंदर पढ़ें

- बेरोज़गारी और बढ़ती क़ीमतों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन 3
- डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की जायज मांगें 4
- दिल्ली राज्य कर्मचारी सम्मेलन 4
- अमरीकी रणनीति में क्वाड की भूमिका 5

एयर इंडिया का निजीकरण – अधिकतम मुनाफे कमाने के लिए ...

पृष्ठ 1 का शेष

पार्किंग के लिये स्थान हैं, साथ ही विदेशों में हवाई अड्डों पर 900 स्थान हैं। दुनियाभर के बहुत व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ज़मीन पर उतरने और पार्किंग के लिये अब कोई नया स्थान उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण नई एयरलाइन ऐसे हवाई अड्डों के लिए उड़ान नहीं भर सकती। इन स्थानों पर कब्ज़ा प्राप्त करने से हिन्दोस्तान और वैश्विक स्तर पर हवाई उड़ानों के बाज़ार में टाटा की हिस्सेदारी तुरंत बढ़ जाती है।

टाटा समूह, इस समय देश में दो एयरलाइनों का संचालन करता है। एक है विस्तारा जो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ संयुक्त उद्यम है। दूसरा है एयर एशिया, जो मलेशिया की एयरलाइन, एयर एशिया के साथ एक संयुक्त उद्यम है। इन दोनों कंपनियों का अधिकतम शेयरधारक टाटा है। एयर इंडिया की तुलना में इन दोनों एयरलाइनों के संचालन का पैमाना काफी छोटा है। घरेलू बाज़ार में इनकी हिस्सेदारी 15 फीसदी से भी कम है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इनका हिस्सा न के बराबर है। एयर इंडिया और ए.आई. एक्सप्रेस का अधिग्रहण करके टाटा समूह हिन्दोस्तानी की सभी एयरलाइनों में शीर्ष स्थान पर पहुंच जायेगा।

हिन्दोस्तानी लोगों की सार्वजानिक सम्पत्ति एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंपने के इस क़दम को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इस तरह से पेश कर रही है जैसे कि उसने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया है, जिसे करने की कोशिश पिछली सरकारों ने की लेकिन असफल रहीं। एअर इंडिया की बिक्री के पिछले सभी प्रयासों को इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा विफल किया गया था, ताकि केंद्र सरकार उनके द्वारा निर्धारित शर्तों पर इसे बेचने के लिए सहमत हो। इस बिक्री पैकेज के द्वारा एयर इंडिया और ए.आई. एक्सप्रेस में हिन्दोस्तान की सरकार के स्वामित्व वाले 100 प्रतिशत शेयरों पर अब टाटा समूह का कब्ज़ा हो गया। पैकेज में एयर इंडिया–एस.ए.टी.एस. एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में सरकार के आधे शेयरों की बिक्री भी शामिल है, जो सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज लिमिटेड के साथ 50–50 प्रतिशत का संयुक्त उद्यम है।

एयर इंडिया के निजीकरण के प्रयास 2000 में शुरू हुए थे। मज़दूर यूनियनों के कड़े विरोध के कारण कुछ समय के लिए इसके निजीकरण को रोक दिया गया था। एयर इंडिया के निजीकरण की योजना को मई 2017 में फिर से सक्रिय किया गया, जब नीति–आयोग ने एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मार्च 2018 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की गठबंधन सरकार ने एयरलाइन में सरकार के 76 प्रतिशत शेयरों को ख़रीदने के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। निजी–ख़रीदार को 49,000 करोड़ के बकाया कर्ज़ का वहन करने की ज़िम्मेदारी थी। इन शर्तों के तहत पूंजीपतियों कि किसी भी समूह ने एयर इंडिया को ख़रीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे नहीं चाहते थे कि सरकार अपने स्वामित्व का कोई भी हिस्सा अपने पास रखे। वे चाहते थे कि बकाया कर्ज़ का एक बड़े हिस्से का वहन सरकार करे।

केंद्र सरकार ने इजारेदार पूंजीपतियों की मांगों को मान लिया और जनवरी 2020 में राज्य के स्वामित्व वाली एयरलाइन की 100 प्रतिशत बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित कीं, जिसमें ए.आई. एक्सप्रेस लिमिटेड में एयर इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और एयर इंडिया एस.ए.टी.एस. एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी भी शामिल है। ख़रीदार द्वारा वहन किये जाने वाले कर्ज़ की राशि को घटाकर 23,286 करोड़ रुपए कर दिया गया। नए विमानों की खरीद के लिए ऋण की यह राशि ली गई थी। यह भी ऐलान किया गया कि बाकी सारा कर्ज़ सरकार वहन करेगी ।

हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों ने इन शर्तों पर भी एयर इंडिया को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे और रियायतें चाहते थे। अक्तूबर 2020 में सरकार ने ऋण की पूर्व–निर्धारित राशि को ख़रीदार द्वारा वहन करने की आवश्यकता को हटाकर बोली की शर्तों में फिर बदलाव किया। बोली लगाने वालों को एयर इंडिया के ऋण की बकाया राशि पर विचार करने के बाद, उसके उद्यम–मूल्य (एंटरप्राइज वैल्यू) की बोली लगाने के लिए कहा गया था।

सरकार ने एयर इंडिया को बेचने के लिए, इस समय को इसलिए चुना क्योंकि यह इजारेदार पूंजीपतियों के लिए बहुत अनुकूल समय है। जनवरी 2020 से कोरोना वायरस की महामारी के कारण लगाए गए यात्रा–प्रतिबंधों की वजह से पूरी दुनिया में एयरलाइन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अधिकांश हवाई अड्डों और एयरलाइनों को अपने परिचालन स्थगित करने पड़े और बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। एयर इंडिया के घाटे में भी भारी उछाल आया है। नतीजतन यह एक ऐसा समय है जब निजी खरीदार, सामान्य समय की तुलना में अपनी बोली की राशि के स्तर को काफी नीचे कर सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बार एयर इंडिया बिक जाए, हिन्दोस्तान की सरकार ने बोलियां आमंत्रित करने से पहले एक निश्चित न्यूनतम आरक्षित मूल्य भी निर्धारित नहीं किया। सरकार ने बोलियां प्राप्त करने के बाद आरक्षित मूल्य तय किया। ऐसा बताया जा रहा है कि आरक्षित मूल्य मात्र 12,900 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था।

पिछले सालों में एयर इंडिया को हुये घाटे और बकाया कर्ज़ों की ओर इशारा करके, इतने कम आरक्षित मूल्य पर एयर इंडिया को बेचने के सरकार के फ़ैसले को उचित ठहराया जा रहा है। हालांकि, सब यह भी जानते हैं कि इस सार्वजनिक उद्यम को बर्बाद करने के उद्देश्य से सरकार के फ़ैसलों के कारण ही संचित नुक़सान हुआ है।

2005 में इंडियन एयरलाइंस को 43 नए विमानों को खरीदने के निर्देश दिए गए, जबकि यह उनकी ज़रूरतों से बहुत अधिक था। अगले वर्ष, एयर इंडिया द्वारा 68 विमानों की खरीद के लिए 50,000 करोड़ रुपये के एक बडे ऋण की व्यवस्था की गई थी, जबकि असली ज़रूरत केवल 28 विमानों की थी। इन ऋणों के वार्षिक ब्याज और मूलधन की अदायगी ने मुनाफ़ा कमाने वाली दोनों एयरलाइनों को घाटे में चलने वाली कंपनियों में बदल दिया।

लगभग उसी समय (2004–2005) में एयर इंडिया के सबसे आकर्षक और मुनाफे कमाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मार्गों और स्थानों विशेष रूप से खाड़ी देशों के मार्ग – निजी और विदेशी एयरलाइनों को देने के लिए सरकार तैयार थी।

एयरलाइन के, वित्तीय हालात तब और भी ख़राब हो गये, जब सरकार ने सभी नियोजित–कर्मचारियों के एकजुट विरोध के बावजूद, 2006 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को विलय करने के लिए मजबूर किया। उस समय इंडियन एयरलाइंस विमानन के क्षेत्र में एक अगुवा की भूमिका में थी, जिसके पास हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के घरेलू बाज़ार का 42 प्रतिशत हिस्सा था। विलय का उद्देश्य था सार्वजनिक कंपनी को कमजोर करके निजी एयरलाइन कंपनियों के मुनाफ़ों को बढ़ावा देन। इंडियन एयरलाइंस को अपने राजस्व का 40 प्रतिशत खाड़ी मार्गों से प्राप्त होता था। सरकार के फ़ैसलों ने इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया।

एयर कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ के महासचिव बी. कादियान ने एयर इंडिया के कर्मचारियों से विचार व्यक्त करते हुये उन्होंने कहा, "इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय ताबूत में आखिरी कील की तरह था" और उन्होंने यह भी बताया कि "निजी खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका यह सुनिश्चित करना था कि इंडियन एयरलाइंस का नाम भारतीय आसमान के नक्शे से ग़ायब हो जाए।"

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय ने दोनों एयरलाइंस को बर्बाद कर दिया। 2007 में विलय के बाद पहले ही वर्ष में कंपनी को 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। एक तरफ निजी एयरलाइंस को एयर इंडिया के बर्बाद होने से बहुत फ़ायदा हुआ और उनकी बाज़ार–हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, दूसरी तरफ एयर इंडिया की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का इस्तेमाल, किसी भी क़ीमत पर एयर इंडिया के निजीकरण करने के फ़ैसले को सही ठहराने के लिए किया गया।

एयर इंडिया के निजीकरण और नागरिक उड्डयन से हिन्दोस्तानी राज्य के पूर्ण रूप से हटने के साथ, अब हवाई–किराए पूरी तरह से ज्यादा से ज्यादा निजी मुनाफ़े बनाने के उद्देश्य से, निर्धारित किए जाएंगे। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने जैसे सामाजिक उद्देश्यों पर विचार तक नहीं किया जाएगा। जिन स्थानों पर उड़ानें आमतौर पर भरी नहीं होती हैं, वहां हवाई टिकट की क़ीमतों में भारी वृद्धि होगी। निजी एयरलाइनों पर पहले से ही, कार्टेल बनाने और एकाधिकार मूल्य निर्धारण की साजिश करने का आरोप लगाया गया है। 2018 में, इंडिगो, जेट एयरवेज और स्पाइसजेट–सभी पर हिन्दोस्तानी प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा, ईंधन–अधिभार दर बढ़ाने के लिए कार्टेल बनाने के लिए, जुर्माना लगाया गया था।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विनाश और निजीकरण सबसे बड़े हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के इशारे पर किया गया है, ताकि उनकी अधिकतम मुनाफ़े की लालच को पूरा किया जा सके। मज़दूरों को नौकरी की और भी अधिक असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा। हवाई यात्रियों को अधिक क़ीमतों का सामना करना पड़ेगा। जनता को बहुत भारी क़ीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि जनता के पैसे से ही, इस भारी बकाया कर्ज़ को चुकाया जाएगा।

http://hindi.cgpi.org/21482

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का प्रकाशन

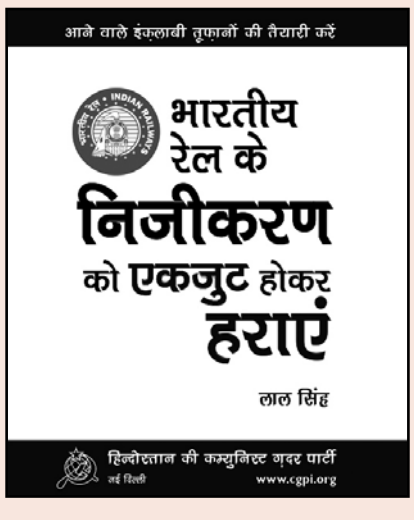

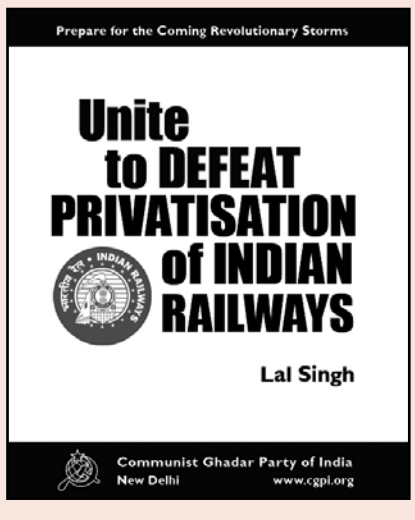

यह पुस्तिका कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा 13 मई, 2018 को दिल्ली में पार्टी की एक सभा में प्रस्तुत की गई थी।

संपर्क : लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फोन : 09810167911, मूल्य 20 रुपये

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के 5वें महाअधिवेशन की रिपोर्ट

हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध
(कीमत 100 रू. और डाक खर्च 40 रू.)
निम्नलिखित पते पर मनीआर्डर या बैंक ट्रांसफर करें
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कालका जी,नई दिल्ली, खाता संख्या : 20066800626, ब्रांच कोड : 00974, IFSC: MAHB0000974

संपर्क करें :– ई–392, लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली – 110020, फोन : 9810167911, 9868811998

बेरोज़गारी और बढ़ती क़ीमतों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन

मेहनतकश लोगों की आजीविका और अधिकारों पर चौतरफा और बढ़ते हमलों के ख़िलाफ़ कम्युनिस्ट और वामपंथी दलों ने 30 सितंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। विरोध का आयोजन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई.), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी–मार्क्सवादी (सी.पी.आई.एम.), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी–मार्क्सवादी लेनिनवादी (सी.पी.आई.–एम.एल.), हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी (सी.जी.पी.आई.), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (ए.आई.एफ.बी.) और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आर.एस.पी.) द्वारा संयुक्त रूप किया गया था।

"पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें नीचे लाओ!", "क़ीमत वृद्धि बंद करो!", "बढ़ती बेरोज़गारी के को ख़तम करो!", "सभी मज़दूरों के लिए न्यूनतम मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करो!", "हड़ताल के हमारे अधिकार पर हमले बंद करो!", "सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में बेचना बंद करो!", "तीन किसान विरोधी कानूनों को तुरंत रद्द करो!", "श्रम संहिताओं को निरस्त करो!" – इन सभी और प्रदर्शनकारियों की अन्य मांगों को बैनरों पर मुख्य रूप से लिखा गया था। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाज़ी की।

रैली में भाग लेने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कोविड–19 संकट के दौरान लोगों को स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने के लिए और लोगों को अपने हाल पर छोड़ देने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में, संकट सबसे बड़े हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के लिए एक वरदान रहा है, जिनका मुनाफ़ा इस दौरान कई गुना बढ़ गया है। सरकार ने लोगों के सभी प्रकार के विरोध को कुचलने के लिए और तीन किसान विरोधी कानूनों और श्रम संहिताओं जैसे जनविरोधी कानूनों को लागू करने के लिए कोविड संकट का इस्तेमाल किया है। वक्ताओं ने पेट्रोल, डीज़ल और सभी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती क़ीमतों के ख़िलाफ़ और सबसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और तीन किसान विरोधी कानूनों और श्रम संहिताओं को तत्काल हटाने की मांग की।

रैली में देश भर के मज़दूरों और किसानों, महिलाओं और नौजवानों से इन हमलों का विरोध करने के लिए एक साथ आने और इन हमलों को हराने के लिए एक शक्तिशाली प्रतिरोध आंदोलन बनाने का आह्वान किया।

सी.पी.आई. महासचिव डी. राजा, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के बिरजू नायक, सी.पी.आई.एम. के प्रो. राजीव कुमार, सी.पी.आई.एम.एल. की सुचेता डे; आर.एस.पी. के दिल्ली राज्य सचिव, शत्रुजीत सिंह और ए.आई.एफ.बी. के दिल्ली राज्य सचिव, धर्मेंद्र कुमार वर्मा, के साथ रैली को कई अन्य कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया।

http://hindi.cgpi.org/21480

किसान आंदोलन – वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ता

पृष्ठ 1 का शेष

श्री डल्लेवाल जी ने मज़दूरों और किसानों की बढ़ती एकता और देश के सभी हिस्सों में हिन्दोस्तानी लोगों के सभी वर्गों से किसान आंदोलन के लिए भारी समर्थन मिलने पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे की राह बताते हुए किसान आंदोलन के संघर्ष को देश के कोने–कोने तक ले जाने के संकल्प की बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों के संघर्ष और सरकार द्वारा उनकी जायज़ मांगों को मानने से इनकार करने से लोगों की नज़र में मोदी सरकार की विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है। उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया कि सरकार अंततः तीन किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर होगी। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं का स्रोत तीस साल पहले शुल्क और व्यापार पर आम समझौता (गैट) पर हस्ताक्षर करके कृषि व्यापार को उदार बनाने का हिन्दोस्तानी सरकार का निर्णय था। वैश्वीकरण और उदारीकरण के कार्यक्रम को पूरी तरह खतम करने की आवश्यकता है। नहीं तो सरकारें मौजूदा कानूनों के स्थान पर नए कानून बनाकर उसी किसान विरोधी एजेंडे को लागू करेंगी। संघर्ष केवल मोदी सरकार के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हर उस सरकार के ख़िलाफ़ है जो बड़े कॉरपोरेट घरानों के हितों की रक्षा मज़दूरों और किसानों की और जनता के हितों के ख़िलाफ़ काम करती है।

सभी आमंत्रित वक्ताओं ने आज हिन्दोस्तान में चल रहे संघर्ष के समर्थन में बात की।

दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ की ओर से आर. एलांगोवन जी ने किसान आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देते हुए कहा कि किसानों की मांग हम सभी लोगों की मांग है। लोगों पर चौतरफा हमलों – किसान विरोधी कानूनों, श्रम संहिताओं, मूल्यवान सार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण और निजीकरण, लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन – की गणना करते हुए उन्होंने इनसे निपटने के लिए मज़दूर–किसान एकता को मजबूत करने का आह्वान किया।

के.ई.सी. के गिरीश भावे जी ने निजीकरण के ख़तरों के सामने सभी क्षेत्रों के मज़दूरों की बढ़ती एकता का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि निजीकरण का विरोध करने वाले सभी मज़दूर यूनियनों और संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन (ए.आई.एफ.ए.पी.) का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि यह अहसास बढ़ रहा है कि निजीकरण पूरी तरह से मज़दूरों, किसानों और हमारे सभी तबकों के हितों के ख़िलाफ़ है और इसका विरोध किया जाना चाहिए।

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स के श्री आर.के. त्रिवेदी जी ने सरकार को बिजली संशोधन अधिनियम 2021 के कार्यान्वयन को रोकने पर मजबूर करने के लिए किसान आंदोलन को बधाई दी। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से किसानों के हितों के ख़िलाफ़ है और उन्होंने समझाया की इससे कृषि उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी, आय घटेगी और किसानों के ऊपर कर्ज़ बढ़ेगा।

तमिलनाडु के किसान नेता श्री गोविंदस्वामी थिरुनावुकारसु जी ने बड़े इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा हमारे प्राकृतिक संसाधनों की अप्रतिबंधित लूट की अनुमति देने और इस तरह पर्यावरण को नष्ट करने और हमारे लोगों को ख़तरे में डालने के लिए सरकार की आलोचना की। दिल्ली की सीमाओं पर और पूरे देश में किसानों के संघर्ष की सराहना करते हुए उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कार्यक्रम को हराने के उद्देश्य से संघर्ष तेज करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट ब्रिटेन) के दलविंदर अटवाल जी ने किसान आंदोलन और बढ़ती मज़दूर–किसान एकता की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानों ने शासकों के झूठे प्रचार का भली–भांति पर्दाफाश किया है।

देश भगत स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी, कनाडा के प्रवक्ता इकबाल सिंह सुंबल जी ने राज्य के हमलों का विरोध करने के लिए किसानों, मज़दूरों और हिन्दोस्तान व विदेशों में रहने वाले सभी देशभक्त हिन्दोस्तानियों को एक मंच पर लाने के लिए एम.ई.सी. के प्रयास की सराहना की।

लोक राज संगठन के उपाध्यक्ष संजीवनी जी ने सवाल किया कि हमारे देश में किस तरह का लोकतंत्र है, जो सरकार को ऐसे कानूनों को पारित करने में सक्षम बनाता है जिनका लाखों लोगों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। लोगों को सुख और रक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। उन्होंने मज़दूरों और किसानों को शासक बनने की, निर्णय लेने की और अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

ग़दर इंटरनेशनल के सलविंदर ढिल्लों जी ने बताया कि, शोषण से मुक्त हिन्दोस्तान का सपना, चाहे शोषक ब्रिटिश हों या हिन्दोस्तानी या दोनों का गठबंधन हो – शहीद भगत सिंह और उनके साथियों का वह सपना अभी भी अधूरा है। उन्होंने कहा की आइए, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएं।

पुरोगामी महिला संगठन की शीना अग्रवाल जी ने आज किसान आंदोलन और संघर्ष के सभी मोर्चों पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। उन्होंने समझाया कि महिलाओं की मुक्ति का मार्ग पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने, हमारे अधिकारों की रक्षा और सभी प्रकार के शोषण से मुक्त समाज में निहित है।

एम.ई.सी. के बिरजू नायक जी ने उन पार्टियों के ख़िलाफ़ आगाह किया जो इस लाइन को बढ़ावा दे रही हैं कि भाजपा मुख्य दुश्मन है। भाजपा को मुख्य शत्रु के रूप में पहचानने का अर्थ है एक बार फिर से धोखा खाना और इस झूठी आशा से लोगों को धोखा देना कि भाजपा की जगह कांग्रेस पार्टी या कोई भाजपा विरोधी गठबंधन किसानों के हितों को आगे बढ़ाएगा। असली विकल्प मज़दूरों और किसानों के गठबंधन को मजबूत करना है, ताकि वह राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले सके, इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों और अन्य सभी निजी मुनाफ़ाखोरों द्वारा हमारे लोगों की लूट को समाप्त कर सके और सभी कामकाजी लोगों के लिए सुरक्षित आजीविका की गारंटी दे सके।

कई प्रतिभागियों ने अपने विचार रखे। उन्होंने इस बैठक के आयोजन में एम.ई.सी. की पहल की सराहना की और किसान आंदोलन की मांगों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। राजस्थान के शिक्षक और किसान नेता हनुमान प्रसाद शर्मा जी ने कहा कि सरकार सत्ताधारी पूंजीपति वर्ग के प्रबंधक के अलावा और कुछ नहीं है और यह उस एजेंडे को लागू करती है जो पूंजीपतियों द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है। अन्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारे अधिकारों पर ये हमले लगातार होते रहे हैं, भले ही कोई भी सरकार सत्ता में रही हो। इसलिए केवल सरकार बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारा निशाना पूंजीपति वर्ग है। प्रतिभागियों ने शहीद भगत सिंह के बलिदान, साहस और दृढ़ विश्वास को याद किया, जिनकी 114वीं जयंती पूरे देश में मज़दूरों और किसानों द्वारा एक दिन पहले मनाया गयी थी। एक युवा कार्यकर्ता ने किसानों के दृढ़ संकल्प और संघर्ष की भावना का जश्न मनाते हुए एक स्व–रचित कविता प्रस्तुत की।

सभी हस्तक्षेपों के अंत में, श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने एक बार फिर चर्चा आयोजित करने के लिए एम.ई.सी. का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बैठक में शामिल सभी प्रतिभागियों से किसान आंदोलन के संदेश को देश के सभी हिस्सों में ले जाने और मज़दूरों और किसानों की एकता बनाने की अपील की।

सुचरिता जी ने सभी प्रकार के शोषण से मुक्त एक नए हिन्दोस्तान के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने, सभी के लिए सुख और रक्षा सुनिश्चित करने वाले मज़दूर–किसान शासन की स्थापना के लिए एक प्रेरक आह्वान के साथ बैठक का समापन किया।

http://hindi.cgpi.org/21459

डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की जायज़ मांगें

महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 1 अक्टूबर से राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था। महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) ने घोषणा की थी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, हड़ताल जारी रहेगी।

रेजिडेंट डॉक्टरों की मुख्य मांग है कि उनकी पढ़ाई की फीस माफ़ की जाए। उनकी दूसरी मांग है कि छात्रावास की अवस्था में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि ये पूरे महाराष्ट्र में बहुत ख़राब है। उनकी तीसरी मांग है कि बी.एम.सी. अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों के वजीफे में से टैक्स को पहले ही नहीं काटा जाना चाहिए। इसके अलावा, डॉक्टरों ने मांग की है कि पूरे महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को कोविड प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए।

मार्ड के प्रवक्ता ने बताया कि वे पिछले 5 महीनों से इन मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य सरकार की ओर से कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। इसी वजह से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मार्ड ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे हड़ताल को बढ़ा देंगे। हालांकि, एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी लेकिन ओ.पी.डी. का कोई काम नहीं किया जायेगा।

5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार करने के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल को रोक दिया।

पिछले दो सालों में, स्वास्थ्य कार्यकर्ता अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और कोविड मरीजों की सेवा करने के

पुणे में अपने अधिकारों के लिये प्रदर्शन करते हुए रेजिडेंट डॉक्टर

लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, जबकि वे खुद वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सभी जानते हैं कि वे असुरक्षित स्थिति में काम करते हैं और अक्सर उन्हें सुरक्षा उपकरण भी नहीं दिये जाते हैं। उन्हें कोरोना योद्धाओं के रूप में सम्मानित किया गया है, लेकिन इस मौखिक तारीफ के अलावा, स्वास्थ्य अधिकारियों ने काम करने की उनकी स्थिति में सुधार के लिए कोई क़दम नहीं उठाये हैं। कई मामलों में तो उनका वेतन महीनों से बकाया है।

डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के सहायक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर समय–समय पर हड़तालें की है और पिछले दो सालों में भी कई हड़तालें की हैं, लेकिन हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को इससे नुकसान न हो। शासक वर्ग ने स्वास्थ्य कर्मियों से किए गये अपने हर वादे को तोड़ने के लिए महामारी को बहाना बनाया है। पूरे देश में यह बार–बार दोहराया गया है कि – स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों की सुनवाई के लिये हड़ताल करते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य कर्मियों की हालतों में सुधार किये बिना और उनकी आवास की अवस्था को बदले बिना ही मज़दूरों के गुस्से को ठंडा करने के लिए बार–बार झूठे वादे करती रही हैं।

हाल ही में 4 सितंबर, 2021 को दिल्ली के एम्स की नर्स यूनियन और कर्मचारी यूनियन ने 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का नोटिस दिया था। उन्होंने 47 मांगें रखी हैं, जिनमें प्रमुख है वेतनमानों और भत्तों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ समानता। यह एम्स के संचालन नियमों के अनुसार है जिसका अधिकारी उल्लंघन कर रहे हैं। उनकी अन्य महत्वपूर्ण और लंबे समय से चली आ रही मांग है कि नर्सों और अन्य कर्मचारियों के पदों की संख्या बढ़ाई जाये। अस्पताल में कई नये चिकित्सा विभाग बनाए गए हैं, जबकि इन सेवाओं के लिए पदों की संख्या जस की तस बनी हुई है।

2021 के मई और जून में मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों ने अपने वजीफे में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी और 6 प्रतिशत वार्षिक की सुनिश्चित बढ़ोतरी (जो मुश्किल से जीवन यापन की लागत में हुई बढ़ोतरी को पूरा करती है), बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और कोविड–19 से संक्रमित अपने परिवारों का मुफ़्त इलाज कराने की मांगों को पूरा करने के लिये प्रदर्शन किया था।

अक्टूबर 2020 में दिल्ली के उत्तरी नगर–निगम द्वारा संचालित हिंदू राव अस्पताल, राजन बाबू टीबी अस्पताल और कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों को अपने वेतनों का भुगतान करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाना पड़ा था, जो कि पिछले चार महीने से बकाया थे! उस समय राजधानी दिल्ली में 5,000 रेजिडेंट डॉक्टरों ने इन अस्पतालों के डॉक्टरों के समर्थन में सांकेतिक हड़ताल की थी। हड़ताल का आह्वान करने से पहले रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सों की यूनियनों ने अस्पतालों के अधिकारियों सहित नगर–निगम के अधिकारियों के सामने कई बार अपनी समस्याएं रखी थीं।

कई राज्यों में रेजिडेंट डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मचारियों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने वेतनों के बकाये के भुगतान, रिक्त पदों को न भरे जाने, रेजिडेंट डॉक्टरों की सेवा अवधि में विस्तार, परीक्षाओं की तैयारी पूरी न कर पाने और परीक्षाओं को प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से पुनर्निर्धारित करने, आदि के बारे में अपनी शिकायतें पेश की हैं।

यह बात निंदनीय है कि समाज की इतनी सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी जायज़ मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है।

http://hindi.cgpi.org/21464

दिल्ली राज्य के मज़दूरों के सम्मेलन ने 25 नवंबर, 2021 को हड़ताल का आह्वान किया :

अपनी आजीविका और अधिकारों पर बढ़ते हमलों के ख़िलाफ़ संघर्ष में एकजुट हों!

हम यहां मज़दूर एकता कमेटी से प्राप्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति द्वारा आयोजित अधिवेशन की रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं।

दिल्ली की ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने 30 सितंबर को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन ने दिल्ली के मज़दूरों, विशेष रूप से अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की गंभीर स्थिति का आकलन किया। सम्मलेन में हमारी आजीविका और अधिकारों पर बढ़ते हमलों के ख़िलाफ़ एकजुट संघर्ष का आह्वान किया गया।

सम्मेलन ने बेरोज़गारी और आजीविका की असुरक्षा की भयानक समस्याओं पर प्रकाश डाला, जिसमें बताया गया कि किस तरह मज़दूरों को कम मज़दूरी पर लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और इसके बावजूद उन पर नौकरी खोने का ख़तरा लगातार बना रहता है। कोविड–19 के संकट ने इन समस्याओं को और भी बढ़ा दिया है। कोविड–19 की महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने मज़दूरों के कष्टों को और बढ़ा दिया है। किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के नहीं होने का मतलब है कि मज़दूरों को खुद के हाल पर छोड़ दिया गया है। दूसरी ओर, सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों की संपत्ति में तेज़ी से वृद्धि हुई है।

सम्मलेन में बताया गया कि सरकार सबसे बड़े इजारेदार कॉरपोरेट घरानों के एजेंडे को ही लागू कर रही है। हमारे किसानों और मज़दूरों पर गंभीर हमला करने वाले किसान विरोधी कानूनों और श्रम संहिताओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कोविड–19 के प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया है। सम्मेलन में निजीकरण और मुद्रीकरण कार्यक्रम की आलोचना की गई, जिसके तहत हजारों करोड़ रुपये की भूमि और सार्वजनिक संपत्ति कॉरपोरेट घरानों को सौंपी जा रही है। यह बताया गया कि निजीकरण का कार्यक्रम बेरोज़गारी और मज़दूरों की आजीविका और अधिकारों पर हमलों को बढ़ावा देगा।

अधिवेशन में दिल्ली की ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाई गई मुख्य मांगें थीं : चार श्रम संहिताओं को ख़ारिज करना, किसान–विरोधी कानूनों को ख़ारिज करना, न्यूनतम मज़दूरी 21,000 रुपए प्रति माह लागू हो, कोविड संकट के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले मज़दूरों को मुआवज़ा मिले, मुफ्त टीकाकरण हो, अनुबंध पर मज़दूरी को समाप्त किया जाये, समान काम के लिए समान वेतन मिले, सभी मज़दूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था पेंशन हो, निजीकरण को समाप्त किया जाये, इत्यादि।

सम्मेलन में हमारी आजीविका और अधिकारों की रक्षा के लिए एक संयुक्त संघर्ष का आह्वान किया गया। 25 नवंबर, 2021 को दिल्ली की सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त हड़ताल करने का आह्वान किया गया।

सम्मेलन का आयोजन सीटू, एटक, ऐक्टू, एच.एम.एस., मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.), यू.टी.यू.सी., टी.यू.सी.सी., ए.आई.यू.टी.यू.सी., आई.सी.टी.यू., सेवा, एल.पी.एफ. और इंटक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

http://hindi.cgpi.org/21485

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810187911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

अमरीकी रणनीति में क्वाड की भूमिका

अमरीका, जापान, हिन्दोस्तान और ऑस्ट्रेलिया के शासनाध्यक्षों ने 24 सितंबर को अमरीका में मुलाक़ात की। यह इन चार देशों की सरकारों के प्रमुखों की पहली बैठक थी, जिसमें वे सब स्वयं एक साथ उपस्थित थे, इस गठबंधन को क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) के नाम से जाना जाता है। इस साल की शुरुआत में इन सरकारों के प्रमुखों ने मार्च में एक ऑनलाइन बैठक भी की थी।

क्वाड पूरी दुनिया पर अपना बेजोड़ वर्चस्व स्थापित करने की अमरीकी रणनीति का एक हिस्सा है और इसकी शुरुआत एशिया को जीतने की भूमिका के रूप में है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमरीका, उभरते हुए चीन को एक मुख्य ख़तरे के रूप में देखता है। शिखर सम्मेलन के अंत में चारों नेताओं द्वारा जारी संयुक्त बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अमरीका चीन को रोकने के लिए क्वाड गठबंधन का इस्तेमाल करने की उम्मीद रखता है।

यह बयान हिन्द–प्रशांत महासागर क्षेत्र और दुनिया में "सुरक्षा और समृद्धि" को, कथित रूप से मजबूत करने के लिए "अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित, एक नियम–आधारित व्यवस्था के समर्थन" इन चार देशों की प्रतिबद्धता पर आधारित है। अमरीका किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं करता है। इसके विपरीत यह नियम–आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधी है। यह उन सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन करता आया है जिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जैसे कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहे उनकी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था अलग भी हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्यूबा से नाकेबंदी हटाने की मांग के प्रस्तावों के बावजूद, अमरीका क्यूबा की अवैध नाकेबंदी जारी को रखे हुए है।

अमरीका ने ईरान की एकतरफा आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। अमरीका ने हर उस देश को सज़ा देने की धमकी दी है, जो ईरान के साथ व्यापार करने की जुर्रत करता है। अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा आक्रामकता, हमले और सैन्य हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, कोरियाई प्रायद्वीप के देश, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अफ़ग़ानिस्तान, इराक, ईरान, लीबिया, सीरिया और सोमालिया के लोगों को भारी विनाश और तबाही का सामना करना पड़ा है।

अमरीका पृथ्वी पर अब तक की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और इसके युद्धपोत दुनिया के सभी समुद्रों और महासागरों में खुल्लम–खुल्ला बिना किसी रोक के स्वतंत्र घूमते हैं और अन्य सभी देशों को, वे चाहे बड़े हों या छोटे धमकी देते हैं। वह अन्य देशों की क्षेत्रीय जल–सीमाओं को मान्यता नहीं देता है, जैसा कि यू.एन.सी.एल.ओ.एस. (संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सहमति से बने समुद्र के क़ानून) द्वारा परिभाषित किया गया है। इस साल की शुरुआत के अप्रैल में हिन्दोस्तान के ख़िलाफ़ एक उकसावे के रूप में अमरीका द्वारा, अपने सातवें जहाजी बेड़े के एक अमरीकी युद्धपोत को लक्षद्वीप के पास हिन्दोस्तानी जल क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए जबरदस्ती भेजा गया था। अमरीका ने सार्वजनिक रूप से और बड़ी बेशर्मी के साथ, यह ऐलान भी किया था कि वह इन जल–क्षेत्रों की

चीन को घेरने के लिये बनाया जा रहा क्वाड गठबंधन

सीमाओं पर हिन्दोस्तान के अधिकारों को मान्यता नहीं देता।

हिन्दोस्तान के साथ–साथ दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के अपनी देश की सीमाओं और क्षेत्रीय जल सीमाओं के बारे में चीन के साथ मतभेद हैं। ये मतभेद उपनिवेशवादी हुकूमत की विरासत हैं। चीन को नियंत्रण में करने के लिए अमरीका इस तरह के मतभेदों का फ़ायदा उठा रहा है और अपने नेतृत्व में इन देशों का चीन के ख़िलाफ़ गठबंधन बनाने के लिए उन्हें उकसा रहा है।

अमरीका ने प्रस्ताव रखा है कि उसके नेतृत्व में एक पूर्वी–नाटो–यानी, अमरीका, जापान, हिन्दोस्तान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का चीन के ख़िलाफ़ एक सैन्य गठबंधन स्थापित किया जाना चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के लोगों को औपनिवेशिक हुकूमत, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके देशों पर बर्बर जापानी कब्ज़े और कोरियाई, वियतनामी और अन्य लोगों के ख़िलाफ़, अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा छेड़े गए क्रूर युद्ध की कड़वी यादें एकदम ताज़ा हैं। वे अमरीका या किसी अन्य साम्राज्यवादी शक्ति के अधीन नहीं होना चाहते। वे बिलकुल नहीं चाहते कि अमरीका और चीन के बीच बढ़ते टकराव में उनके देश उलझें।

इस हक़ीक़त का एहसास करते हुए कि दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देश चीन के ख़िलाफ़ अमरीकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, अमरीका, एशिया पर अपना वर्चस्व जमाने की अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है।

क्वाड गठबंधन की स्थापना का अंतर्निहित उद्देश्य है चीन से दोनों ही हालतों में, चाहे ज़मीन पर या महासागरों में एक सैन्य शक्ति के रूप में लड़ना। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों को इस तरह के गठबंधन में लामबंध करने के लिए, अमरीका एक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता देने के बहाने, उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहा है। अमरीका दावा करता है कि यह सहायता बिना किसी शर्त और स्वार्थ के एशियाई देशों और लोगों को प्रदान की जाएगी – कहने के लिए यह तरीक़ा, इन देशों में बुनियादी ढांचे के विकास में चीन के निवेश के तरीक़े से बिलकुल अलग है।

चीन ने एशिया, अफ़्रीका और यूरोप के कई देशों को शामिल करते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नामक बड़े पैमाने पर एक बुनियादी ढांचे के विकास की पहल की है। क्वाड शिखर सम्मेलन ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक पर्याय के रूप में आसियान देशों में बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने का निर्णय लिया।

क्वाड शिखर सम्मेलन ने 5जी संचार, सौर–ऊर्जा आदि के साथ, उच्च तकनीकी क्षेत्रों में चार देशों के बीच सहयोग की घोषणा की। अमरीका इन क्षेत्रों में चीन को चुनौती देना चाहता है।

चीन ने आसियान के देशों में भारी मात्रा में कोविड टीकों की आपूर्ति की है। क्वाड शिखर सम्मेलन ने भी ऐलान किया कि हिन्दोस्तान अक्तूबर से इन देशों को टीकों की आपूर्ति करेगा। हिन्दोस्तान में टीकों के उत्पादन का वित्त–पोषण अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाएगा।

क्वाड शिखर सम्मेलन में निर्बाध–आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने की बात की गई। चीन दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला के साथ–साथ कई औद्योगिक वस्तुओं में महत्वपूर्ण तत्वों का उत्पादक है। चीन में इस समय उत्पादित आपूर्ति–श्रृंखलाओं के महत्वपूर्ण तत्वों के उत्पादन को अमरीका ने हिन्दोस्तान में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पेश किया है।

क्वाड गठबंधन की स्थापना का अंतर्निहित उद्देश्य है चीन से दोनों ही हालातों में, चाहे ज़मीन पर या महासागरों में एक सैन्य शक्ति के रूप में लड़ना। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों को इस तरह के गठबंधन में लामबंध करने के लिए, अमरीका एक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता देने के बहाने, उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहा है।

संक्षेप में, अमरीका दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर, चीन के साथ अपने टकराव में हिन्दोस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है।

अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन द्वारा ए.यू.के.यू.एस. नामक एक नए सैन्य गठबंधन के गठन की घोषणा के केवल एक सप्ताह बाद ही क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह नया गठबंधन खुले तौर पर चीन के ख़िलाफ़ और चीन पर लक्षित है और इसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया को एक आधार के रूप में इस्तेमाल करते हुए हिन्द और प्रशांत महासागरों में चीन को सैन्य रूप से चुनौती देना है।

दस साल पहले, तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने "एशिया की धुरी" नामक रणनीति की घोषणा की थी। अमरीका ने अपने अधिकांश सशस्त्र बलों को हिंद–प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है। अमरीका ने जापान के साथ मौजूदा सैन्य–संधि के अलावा, ऑस्ट्रेलिया और हिन्दोस्तान के साथ अलग–अलग रणनीतिक सैन्य गठबंधन स्थापित किए हैं। चारों देश हिंद महासागर के साथ–साथ प्रशांत महासागर में नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। अब अमरीका ने एक नए ए.यू.के.यू.एस. सैन्य गठबंधन की स्थापना की है।

हिन्दोस्तानी पूंजीपति ए.यू.के.यू.एस. के साथ सैन्य गठबंधन स्थापित कर, एक ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। समाचार रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अमरीका ने हिन्दोस्तान में कश्मीर या लद्दाख में अमरीकी सैन्य अड्डे उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इससे पता चलता है कि अमरीकी क्षेत्र के अन्य देशों के ख़िलाफ़ अपने युद्धों में हिन्दोस्तान को उलझाना चाहता है। हिन्दोस्तानी लोगों को यह मांग करनी चाहिए कि हिन्दोस्तान, अमरीका के साथ अपने रणनीतिक गठबंधन को समाप्त कर दे।

अमरीका ने एशिया पर विजय की अपनी रणनीति को पूरा करने के लिए क्वाड की स्थापना की है। अमरीका, हिन्दोस्तान और चीन के बीच के अंतर्विरोधों को और तेज़ करने की कोशिश करेगा। अमरीका, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में अपने बाज़ारों और एशिया में प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, हिन्दोतानी पूंजीपति वर्ग की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। सच तो यह है कि कई देशों को इस बात का कड़वा तजुर्बा है कि कैसे अमरीका ने अपने रणनीतिक साम्राज्यवादी मंसूबों के हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल किया और जब उसका मतलब निकल गया, तो फिर उनके पीठ में छुरा भोंका।

क्वाड इस क्षेत्र में अमरीकी साम्राज्यवाद के मंसूबों को पूरा करने के लिए छेड़े गए युद्धों में हिन्दोस्तान के उलझने के ख़तरों को और बढ़ाता है। हिन्दोस्तान को क्वाड से बाहर निकलना होगा।

http://hindi.cgpi.org/21468

मज़दूर एकता लहर के पाठकों से अनुरोध

अनेक साथी मज़दूर एकता लहर के बैंक खाते में आनलाईन ट्रांस्फर से पैसे भेज रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि जो साथी पैसे भेजें, वे इसकी पूरी सूचना हमें दें। पैसे भेजने वाले के नाम या फोन नंबर की पूरी जानकारी, बैंक से नहीं मिल पाती। इसलिये आप सभी साथियों से अनुरोध है कि पैसा ट्रांस्फर करके **मज़दूर एकता लहर** के वाट्सएप्प नंबर-9868811998 पर सूचना अवश्यक दें या 9810167911 पर फोन से सूचित करें।

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT. U (SE)-38/2018-20

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Oct, 2021 Date of publish - 16 Oct, 2021

To

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020।
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें : ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में किसानों पर हो रहे खूंखार हमले की कड़ी निंदा करें

3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी, जब राज्य के उपमुख्यमंत्री के एक काफिले ने यहां पर उनके दौरे का विरोध कर रहे किसानों को जानबूझकर टक्कर मार दी थी। कई को गंभीर चोटें आई हैं। काफिले के सदस्यों ने शांतिपूर्वक विरोध कर रहे किसानों पर गोलियां चलाईं, जिसमें कई अन्य लोग घायल हो गए। क्षेत्र के भाजपा सांसद जो एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका बेटा जो काफिले का नेतृत्व कर रहा था उसने खुलेआम घोषणा की कि किसानों को पता होना चाहिए कि वे किसको चुनौती दे रहे हैं – वह अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में डींग मार रहा था जिसको राज्य में सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं।

उसी दिन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने अपनी पार्टी के सदस्यों को और सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके, राज्य के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठियां लेकर हमला करने के लिए उकसाया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उन्हें कुछ दिन जेल में बिताने की चिंता नहीं करनी चाहिए, यदि ज़रूरत पड़ी, तो उन्हें "हीरो" भी बना दिया जाएगा।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करती है। हम किसान आंदोलन से जुड़े बहादुर किसानों पर खूनी हमले आयोजित करने के लिए, अराजकता और हिंसा फैलाने के हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के खुलेआम आह्वान की निंदा करते हैं।

केंद्र सरकार से तीन किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने की अपनी न्यायोचित मांग के समर्थन में, किसान एक साल से अधिक समय से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के संघर्ष को पूरे देश में श्रमिकों और मेहनतकश लोगों के अन्य सभी वर्गों के बीच बढ़ता समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार, जिस ने किसानों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया है, उसके अहंकारी और अड़ियल रवैये के ख़िलाफ़ पूरे देश की 500 से अधिक किसान यूनियनों के संयुक्त संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया है कि जब–जब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें जनसभाएं आयोजित करेंगी वहां विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। संयुक्त किसान मोर्चे के इस आह्वान के समर्थन में किसानों की प्रतिक्रिया, बहुत ही जबरदस्त रही है। इन परिस्थितियों में किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें, जानबूझकर हिंसक घटनाओं को भड़का रही हैं। इसलिए, 28 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री की करनाल यात्रा का विरोध कर रहे किसानों के ख़िलाफ़, हरियाणा पुलिस ने क्रूर हिंसा और हमले का आयोजन किया। मुख्यमंत्री के दौरे के प्रभारी सरकारी अधिकारी को सुना गया कि वह पुलिस से कह रहा है कि वह किसानों के सिर फोड़ दे।

लखीमपुर खीरी में जो हुआ वह कुछ नया नहीं है। हिन्दोस्तानी राज्य ने किसानों के ख़िलाफ़ हिंसा आयोजित करने और फिर हिंसा के लिए किसानों को ही दोषी ठहराने की नीति का पालन किया है।

दस महीने पहले जब किसानों ने घोषणा की थी कि वे 26 नवंबर को किसान विरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़ दिल्ली आएंगे तो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने पंजाब–हरियाणा सीमा पर किसानों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर हिंसा आयोजित की थी। पुलिस ने महामार्ग को खोद दिया, सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी और किसानों के ख़िलाफ़ पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले छोड़े। सरकारों ने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे किसी दुश्मन देश के साथ युद्ध कर रही हों। लेकिन इन सब खूनी कोशिशों के बावजूद सरकारें किसानों को दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचने से रोकने में नाकाम रहीं।

फिर 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने जानबूझकर अराजकता और हिंसा फैलाने की योजना बनाई ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जाये और उनमें फूट डाली जा सके। इस नापाक मक़सद के लिए उसने सबसे पहले किसानों को दिल्ली में किसान रैली आयोजित करने की अनुमति दी। आखिरी समय पर जानबूझकर रैली के रास्ते को बदल दिया गया जिससे कुछ किसान लाल किले तक पहुंच गए। इसने रास्ते में विभिन्न स्थानों पर टकराव की घटनाओं का भी आयोजन किया। फिर इसने निरंतर प्रचार किया कि कैसे किसान राष्ट्र–विरोधी थे। इसका उद्देश्य था देश की व्यापक जनता की नज़र में किसान आंदोलन को बदनाम करना।

हमारे देश के किसानों के एकजुट, जुझारू संघर्ष को सभी वर्गों के लोगों का बढ़ता समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन को कमज़ोर करने और किसानों के संघर्ष को कुचलने के लिए हिन्दोस्तानी राज्य अराजकता और हिंसा फैला रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसानों के ख़िलाफ़ इस संगठित और उत्तेजक हिंसा के लिए शासक ही ज़िम्मेदार है।

http://hindi.cgpi.org/21457

रेल चालकों का 10वां अधिवेशन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ

2 अक्तूबर, 2021 को दिल्ली में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.) के दिल्ली डिविजन का 10वां अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लखनऊ मंडल से मुख्य अतिथि, श्री संतोष सिंह हांडा शामिल हुए। अधिवेशन की अध्यक्षता कामरेड रामशरण ने की और मंच संचालन कामरेड सूरज कौशिक ने किया।

इस अधिवेशन में दिल्ली मंडल की सभी ब्रांचों से आये 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मंडल की समस्याओं और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की गयी। वक्ताओं ने कहा कि वे रेलवे में निजीकरण करने के क़दमों का विरोध करते हैं। इन क़दमों में शामिल हैं सहायक रेल चालक से गार्ड का काम करवाना, ड्यूटी के घंटों को बढ़ाना, कम स्टाफ से ज्यादा से ज्यादा काम करवाना, डीजल इंजन के चालकों से इलैक्ट्रिक इंजन चलवाना और इलैक्ट्रिक इंजन चालक से डीजल इंजन चलवाना। उन्होंने इन सभी क़दमों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि ये सब नीतियां देश–विरोधी नीतियां हैं और इनके ख़िलाफ़ सभी मज़दूरों को मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा।

इस अधिवेशन में 6 लोगों की सब्जेक्ट कमेटी की ओर से जोनल सचिव पदम सिंह गंगवार ने सदन में प्रस्ताव रखा। 17 लोगों की दिल्ली मंडल की कमेटी को चुना गया, जिसका समर्थन उपस्थित प्रतिनिधियों ने हर्षोल्लास से किया। कमेटी के पदाधिकारियों को भी चुना गया।

अधिवेशन का समापन "इंक़लाब ज़िन्दबाद!" "ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन ज़िन्दाबाद!" के नारों से हुआ।

http://hindi.cgpi.org/21470

Internet Editions

Mazdoor Ekta Lehar (Hindi Fortnightly) http://www.hindi.cgpi.org
Mazdoor Ekta Lehar (Punjabi) http://www.punjabi.cgpi.org
Thozhilalar Ottrumai Kural (Tamil) http://www.tamil.cgpi.org
Mazdoor Ekta Lehar (English) http://www.cgpi.org
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911